economies like India. At this point ot time, a final decision on participation in the Asia-EU Summit has not been taken.

(d) and (e) the criteria for expansion of membership of the ASEAN Regional Forum (ARF) is still under consideration by ASEAN. We have taken up the matter of India's membership of ARF with ASEAN and of India's participation in Asia-EU Summit with both ASEAN and EU partners and have indicated that in any discussions on regional security and in representative Asia-EU Summit, India should be included.

गुजरात में चावल मिलों की स्थापना

6205. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात के कुछ जिलों में चावल मिलों की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त योजनाओं के लिए राज्य के किन-किन जिलों का चयन किया है; और

(ग) इस समय गुजरात में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक कुल कितनी चावल मिलें चल रही हैं और उनका वार्षिक उपादन कितना-कितना है तथा ये राज्य के किन-किन जिलों में स्थापित की गई हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी नहीं। भारत सरकार देश में चावल मिलों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात में अहमदाबाद, खेड़ा, भड़ौच, बड़ौद सूरत, वलसाड़ और साबरकंठा जिलों में 1091 चावल मिलें चल रही हैं। ये सभी मिलें निजी क्षेत्र में हैं और वर्ष 1994-95 में इन्होंने कुल मिलाकर लगभग 11.25 लाख टन वार्षिक उत्पादन किया।

मछुआरों द्वारा हड़ताल किए जाने के संबंध में समाचार

6206. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1995 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "80 लैक फिशरमैन प्लानिंग इनडेफिनिट स्ट्रिर इन मिड एप्रैल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में सरकार द्वारा घोषित नयी नीति के विरोध में देश के पारंपरिक मछुआरों द्वारा हड़ताल करने के बारे में सरकार को सूचित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को और अधिक जटिल बनने से रोकने तथा बातचीत द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए पिछड़े वर्ग के छोटे मछुआरों को आमंत्रित करने की कोई पहल की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यम के खिलाफ राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्रवाई कमेटी के प्रतिनिधियों को 18 मई, 1995 को सभी बकाया मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मध्य प्रदेश में चावल मिलों की स्थापना

6207. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में चावल मिलें स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के किन-किन जिलों तथा किन-किन स्थानों पर इन्हें स्थापित किया जाएगा; और

(ग) मध्य प्रदेश में इस समय कितनी चावल मिलें चल रही है और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी नहीं। सरकार देश में चावल मिलों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 6042 चावल मिलें चल रही है। इन मिलों के उत्पादन आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

Setting up of rices mills in Punjab

6208. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new rice mills in the country, particularly in Punjab;

(b) is so, the details thereof, district-wise and location-wise;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) the total amount proposed to be spent on these mills; and

(c) what concrete steps Government propose to take to set up more rice mills is Punjab?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No, Sir. Government of India is not directly involved in setting up of rice mills in the country.

(b) Does not arise.

(c) Government encourages private enterpreneurs to set up rice mills and has therefore no proposal to set up rice mills directly.

(d) and (e) Do not arise.

AIMS and Objectives of Setting up of Police Pickets

6209. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Times of India dated the 14th March, 1995 under the caption. "No relief for women at police pickets";

(b) if so, the facts thereof;

(c) the action taken by Government against the guilty home guards and the police cops manning that picket; and

(d) whether there is any proposal to keep proper watch on the functioning of police pickets in Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) Yes, Sir.

(b) A lady approached the police picket staff at Nizamuddin Bridge at about 5.50 pm on 12.3.95 with the complaint that three men in a Maruti Vehicle bearing registration Maruti No. DL-2CD- 4042 were following her car and were passing lewd comments at her. The said car had by then, according to the lady, crossed the picket. It was a Police Constable who attended to her and passed the necessary wireless message to the South District Control Room at about 5.57 PM whereafter the lady immediately left without leaving her name and address.

(c) Police Commissioner, Delhi has been instructed to get an enquiry conducted at a senior level into the complaint. He has also been directed to take effective action against errant policemen for any lapses in the handling of this complaint.

(d) All Assistant Commissioners of Police and SHOs pay surprise visits to the Police pickets of their area. The functioning of these pickets is also closely monitored by senior officers of Delhi Police through surprise checks.

Cases About Missing Women in Rohini Police Station

6210. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of kidnapping/ missing of girls/ women registered/ reported in the Sector-VII, Rohini Police Station, Delhi from the 1st April, 1994 to 31st March, 1995;

(b) how many of these have been traced;